आपकी खबरों का संसार...

अतुल्य संसार

संस्करणः जयपुर

हिन्दी समाचार पत्र...

RNI No.-RJHIN/2015/63826

web: www.atulyasansar.com

Digital Edition

www.liveworldnews.in

वर्षः 11 | अंकः 08 | जयपुर, बुधवार 22 जुलाई, 2026 | मूल्यः 2 रुपए | पृष्ठः 4

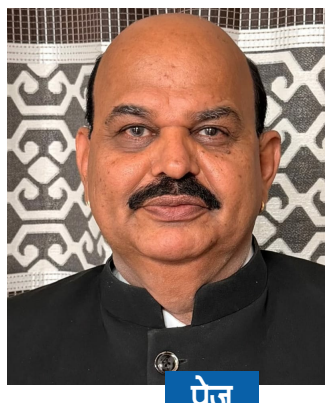

चेक अनादरण ... पेज 2

विप्र फाउण्डेशन... पेज 3

धर्मेंद्र-प्रधान के इस्तीफे की मांग पर सड़कों पर उतरे कांग्रेसी

जयपुर में प्रदर्शन के बाद गहलोत-डोटासरा सहित कई नेता पुलिस हिरासत में; प्रदेशभर में हुआ विरोध-प्रदर्शन

जयपुर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर राजस्थान में कांग्रेस ने मंगलवार को प्रदेशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने सभी जिला मुख्यालयों पर धरना-प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और शिक्षा व्यवस्था समेत अलग-अलग मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। राजधानी जयपुर में अंबेडकर सर्किल पर आयोजित प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी शामिल हुए। वहीं, प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल भी तैनात रहा। धरने के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और कांग्रेस नेताओं को पुलिस बस में लेकर विद्याधर नगर थाने ले गई।

प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा- देश की शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर केंद्र सरकार का रवैया निराशाजनक रहा है। उन्होंने कहा- छात्रों और युवाओं से जुड़े मामलों में लगातार विवाद सामने आने के बावजूद सरकार प्रभावी कदम उठाने में असफल रही है। उन्होंने आरोप लगाया- शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही के बजाय केंद्र सरकार विपक्ष के सवालों से बच रही है।

डोटासरा बोले- मंत्री के इस्तीफा नहीं देने तक विरोध जारी

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा- जब तक छात्रों और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर जवाबदेही तय नहीं होती और केंद्रीय शिक्षा मंत्री अपने पद से इस्तीफा नहीं देते। तब तक पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध जारी रखेगी।

40 मिनट प्रदर्शन के बाद हिरासत में लिया

कांग्रेसी कार्यकर्ता शाम को अंबेडकर सर्किल पर धरने पर बैठ गए। जहां लगभग 40 मिनट के धरने के बाद पुलिस प्रशासन ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत दो दर्जन से ज्यादा कांग्रेसी नेताओं को हिरासत में ले लिया। इस दौरान कांग्रेसी नेता पुलिस की बस के सामने आ गए और कांग्रेस के सीनियर नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध करने लगे। इस दौरान पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर कांग्रेसी नेताओं को खदेड़ा और कांग्रेसी नेताओं को लेकर विद्याधर नगर थाने पहुंची।

पूरे राजस्थान में हुआ प्रदर्शन

बता दें कि कांग्रेस की ओर से यह विरोध जयपुर के साथ प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर एक साथ हुआ। स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग दोहराई। जयपुर के अंबेडकर सर्किल पर बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी, विधायक, पूर्व विधायक, विभिन्न प्रकोष्ठों के प्रतिनिधि और कार्यकर्ता एकत्रित हुए। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग की।

पंचायत-निकाय चुनाव से पहले युवाओं को साधेगी सरकार

वार्ड-पंचायत स्तर पर आयोजित होंगे क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी खेल; कराना होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

जयपुर। पंचायत-निकाय चुनाव से पहले सरकार युवाओं को साधने के लिए खेलों का सहारा लेने जा रही है। इसे लेकर सीएम भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को युवा सुयोग कार्यक्रम लॉन्च किया। कार्यक्रम के तहत वार्ड और पंचायत स्तर पर क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी और फुटबॉल जैसे खेलों का आयोजन होगा। खेलों में हिस्सा लेने के लिए युवाओं को युवा सुयोग प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सीएमआर में लॉन्चिंग के मौके पर सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा- हम युवाओं पर नीतियां सौंपेंगे नहीं, बल्कि उनके खेल के आधार पर खेल की नीतियां तैयार करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा- प्रदेश के युवाओं की शक्ति को सामर्थ्य में बदलने के लिए युवा सुयोग प्लेटफॉर्म सही अवसर और सही मंच उपलब्ध कराएगा। उन्होंने कहा- शहर में वार्ड और गांवों में पंचायत स्तर पर खेलों का आयोजन होगा। वहीं इसमें विजेता रहने वाली टीमें विधानसभा क्षेत्र स्तर पर अपना हुनर दिखाएंगी और युवाओं को आगे ब?ने का मौका मिलेगा।

जिला स्तर पर बनेंगे क्लब

युवा सुयोग कार्यक्रम के तहत सरकार प्रदेश के हर गांव, हर वार्ड के युवाओं की टैकिंग करेगी। जिला स्तर पर सुयोग युवा क्लब स्थापित किए जाएंगे। इनमें सुयोग प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन करने वाला प्रत्येक युवा सदस्य होगा। ये जिला क्लब ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत स्तर और शहरी क्षेत्रों में वार्ड स्तर के युवा क्लबों से जुड़ेंगे। बगरू विधानसभा क्षेत्र और बारां जिले से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मंगलवार को इसकी शुरुआत की गई। सीएम ने कहा- इसके लिए स्कूल, कॉलेज और पंचायत और वार्ड के खेल मैदानों की डिजिटल पहचान भी की जाएगी।

जयपुर में फायर सेफ्टी नियम तोडने पर 4 संस्थान सीलः होटल कर्मा, प्रयास-चिन्मय कोचिंग 180 दिन के लिए सील, 2500 नोटिस किए थे जारी

जयपुर। जयपुर नगर निगम ने फायर सेफ्टी नियमों की अनदेखी करने वाले 4 संस्थानों को 180 दिन के लिए सील कर दिया। नगर निगम ने मंगलवार को रिद्धि-सिद्धि स्थित प्रयास कोचिंग संस्थान और चिन्मय ट्यूटोरियल्स के साथ धावास स्थित कर्मा होटल और गोपालपुरा स्थित जनपथ लाइब्रेरी को सील किया। मौके पर नगर निगम की फायर शाखा और विजिलेंस टीम मौजूद रही। नगर निगम में फायर शाखा के उपायुक्त प्रवीण कुमार ने बताया- शहर में बिना फायर एनओसी और आवश्यक अग्नि सुरक्षा उपकरणों के संचालित हो रहे भवनों के खिलाफ लंबे समय से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य भवन मालिकों को जागरूक करना और सार्वजनिक भवनों में आग से सुरक्षा के मानकों का पालन कराना है। इससे पहले नगर निगम ने करीब 2500 भवन मालिकों को नोटिस जारी किए थे, जिनके पास फायर एनओसी नहीं थी या भवनों में

निर्धारित फायर सेफ्टी उपकरण उपलब्ध नहीं थे। नोटिस की निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद भी जिन भवन मालिकों ने नियमों का पालन नहीं किया, उनके खिलाफ अब सीलिंग की कार्रवाई शुरू की गई है।

संस्थानों में फायर एनओसी नहीं मिली

उपायुक्त प्रवीण कुमार ने बताया- जिन चार संस्थानों को सील किया है, वहां बिना फायर एनओसी और अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही थीं। इससे छात्रों, कर्मचारियों और आम लोगों की सुरक्षा पर खतरा था। इसी कारण इन भवनों को 180 दिनों के लिए सील करने का निर्णय लिया गया।

नियम तोडने वालों पर जारी रहेगी कार्रवाई

नगर निगम ने कहा- फायर सेफ्टी नियमों का पालन नहीं करने वाले अन्य संस्थानों के खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। निगम ने भवन मालिकों से अपील की है कि वे समय रहते फायर एनओसी हासिल करें। भवनों में सभी आवश्यक अग्नि सुरक्षा उपकरण स्थापित करें, ताकि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में जनहानि से बचा जा सके। नगर निगम अधिकारियों ने कहा- सार्वजनिक उपयोग वाले भवनों में फायर सेफ्टी मानकों से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर सीलिंग सहित अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

हाईकोर्ट ने ओआईसी से पूछा-फाइल कहां है, बोला नहीं हैः कोर्ट नाराज, कहा-अधिकारी न्यायालय को गंभीरता से नहीं ले रहे

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने विधवा महिला की फैमिली पेंशन से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के अधिकारियों के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई। अदालत ने कहा कि जिस तरीके से विभाग का अधिकारी बिना तैयारी के कोर्ट में पेश हुआ, उससे साफ लगता है कि राज्य के अधिकारी न्यायालय की कार्यवाही को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। यह टिप्पणी जस्टिस गणेश राम मीणा की अदालत ने गंगा देवी की याचिका पर सुनवाई करते हुए की। दरअसल, शनिवार को वकीलों के कार्य बहिष्कार के कारण सरकारी वकील की अनुपस्थिति में पेंशन एवं पेंशन कल्याण विभाग के एएओ और मामले के ऑफिसर इन चार्ज हमीर सिंह कोर्ट में पेश हुए। सुनवाई के दौरान जब कोर्ट ने उनसे विभाग की ओर से दाखिल जवाब और याचिकाकर्ता के दावे से जुड़े सरकारी आदेशों, अधिसूचनाओं के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि उनके पास इनमें से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। कोर्ट ने इसके बाद अधिकारी से पूछा

कि क्या उन्होंने OIC के कर्तव्यों और राज्य सरकार की लिटिगेशन पॉलिसी पढ़ी है। इस पर अधिकारी ने स्वीकार किया कि उन्होंने कभी लिटिगेशन पॉलिसी नहीं देखी। इस पर अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह विभागीय लापरवाही का स्पष्ट उदाहरण है।

कोर्ट ने कहा- यह स्थिति स्वीकार्य नहीं

हाईकोर्ट ने कहा कि यह मामला किसी सामान्य विवाद का नहीं, बल्कि एक विधवा की फैमिली पेंशन का है। ऐसे संवेदनशील मामले में भी विभाग का अधिकारी बिना आवश्यक रिकॉर्ड और जानकारी के अदालत में उपस्थित हुआ, जो स्वीकार्य नहीं है। अदालत ने कहा कि यदि किसी कारण से सरकारी वकील अदालत में मौजूद नहीं हों, तो संबंधित **OIC** को पूरी केस फाइल, सभी आवश्यक आदेश, अधिसूचनाएं और मामले के तथ्यों की पूरी जानकारी के साथ उपस्थित होना चाहिए। साथ ही जवाब समय पर दाखिल किया जाना चाहिए, ताकि न्यायिक प्रक्रिया में अनावश्यक देरी न हो।

मुख्य सचिव और विभाग को भेजा आदेश

हाईकोर्ट ने कहा कि मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव और निदेशक, पेंशन और पेंशन कल्याण विभाग को आदेश की कॉपी भेजने के निर्देश देते हुए कहा कि सरकार सभी विभागों के **OIC** को उनकी जिम्मेदारियों के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं, ताकि भविष्य में इस तरह की लापरवाही दोबारा न हो। मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त 2026 को होगी।

जयपुर में कुत्ते-बिल्ली का रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर लगेगा जुर्माना

एंटी-रेबीज टीकाकरण जरूरी, नगर निगम के पास हर पालतू पशु का होगा रिकॉर्ड

जयपुर। जयपुर में पालतू कुत्ते-बिल्ली का रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर 5000 रुपए जुर्माना लगेगा। 30 सितंबर के बाद से यह लागू होगा। नगर निगम कमिश्नर ओम कसेरा ने कहा-यह कदम शहर को रेबीज मुक्त बनाने, पालतू पशुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उनके स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड को व्यवस्थित रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। इसके साथ ही फ्रेंडशिप-डे के मौके पर 2 अगस्त को शहर का सबसे बड़ा पेट कार्निवल आयोजित किया जाएगा, जहां मौके पर ही रजिस्ट्रेशन, वैक्सीनेशन, हेल्थ चेकअप और पेट एडॉप्शन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

रेबीज जैसी गंभीर बीमारी की रोकथाम के लिए उठाया कदम

कमिश्नर ओम कसेरा ने बताया- नगर निगम की नई व्यवस्था के तहत शहर में सभी पालतू कुत्तों और बिल्लियों का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। निगम के पास हर पालतू पशु का रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा, जिसमें उसके टीकाकरण और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी

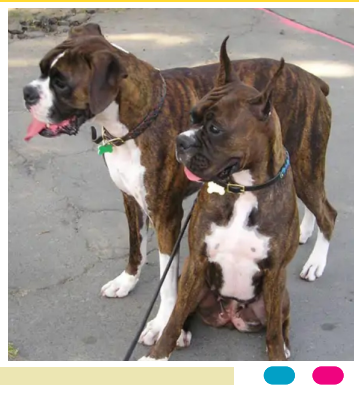

दर्ज होगी। इससे न केवल पालतू पशुओं की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि रेबीज जैसी गंभीर बीमारी की रोकथाम में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह नियम किसी प्रकार की सख्ती के लिए नहीं, बल्कि जिम्मेदार पेट ओनरशिप को बढ़ावा देने और शहर में बेहतर पशु प्रबंधन व्यवस्था विकसित करने के लिए लागू किया जा रहा है। नगर निगम ने लोगों से अपील की है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने पालतू पशुओं का रजिस्ट्रेशन करवा लें, ताकि बाद में किसी प्रकार की कार्रवाई या जुर्माने का सामना न करना पड़े। नगर निगम ने पेट शॉप, डॉग, कैट ब्रीडर और केनल संचालकों के लिए भी नए नियम लागू किए हैं। अब सभी संचालकों के लिए एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया में पंजीयन अनिवार्य होगा। किसी भी श्वान या बिल्ली को खरीददार को सौंपने से पहले उसका नगर निगम में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर तीन महीने से कम उम्र का पिल्ला या बिल्ली का बच्चा बेचा जाता है तो खरीददार से रेबीज वैक्सीनेशन करवाने का शपथ-पत्र लेना भी अनिवार्य होगा।

5000 रुपए तक का जुर्माना

नगर निगम ने रजिस्ट्रेशन और जुर्माने की व्यवस्था भी तय कर दी है। नए पंजीयन के लिए 1000 रुपए प्लस जीएसटी हर साल शुल्क देना होगा, जबकि सालाना नवीनीकरण के लिए 500 रुपए प्लस जीएसटी निर्धारित किए गए हैं। बिना रजिस्ट्रेशन पाए जाने पर 5000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। नियमों के उल्लंघन पर 2000 रुपए का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जा सकेगा।

मौसमी बीमारियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु जिले में नियमित रूप से एंटीलार्वा गतिविधियों का संचालन

अतुल्य संसार नेटवर्क

जयपुर। मानसून में मच्छरों के प्रजनन की संभावना बढ़ने के मद्देनज़र जिले में मौसमी बीमारियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु नियमित रूप से एंटीलार्वा गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम डॉ. रवि शेखावत एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय डॉ. मनीष मित्तल ने बताया कि मौसमी बीमारियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चिकित्साकर्मियों द्वारा निरंतर सोर्स रिडक्शन, एन्टीअडल्ट व जागरूकता के लिए आईईसी की गतिविधियाँ आयोजित की जा रही हैं। इस दौरान आमजन को मौसमी बीमारियों के प्रति जागरूक किया जा रहा है तथा जिला व ब्लॉक स्तर से मोनिटरिंग और सुपरविजन किया जा रहा है।

लोकतंत्र को लाठियों से नहीं चलाया जा सकता- कुँवर गोरधन सिंह रीठौटी

अतुल्य संसार नेटवर्क

दीपचंद शर्मा कुम्हेर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं जिला परिषद सदस्य कुँवर गोरधन सिंह रीठौटी ने कहा की जंतर-मंतर पर छात्रों के साथ जो कुछ हुआ, उसने पूरे देश का सिर शर्म से झुका दिया। अपनी बात रखने पहुँचे युवाओं के साथ बल प्रयोग और लाठियों से उनके सर फोड़ना, बेटियों को भी नहीं बक्शा गया, कार्रवाई की सामने आई तस्वीरों ने देश के हर नागरिक को विचलित किया है। सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार को यह समझना होगा कि छात्र इस देश के दुश्मन नहीं, बल्कि भविष्य हैं। यदि युवाओं के सवालों का जवाब संवाद की जगह लाठी से दिया जाएगा, तो यह लोकतंत्र की आत्मा पर आघात होगा । जब सरकार जनता की आवाज़ सुनना बंद कर देती है, तब विरोध की आवाज़ें और बुलंद होती हैं। सत्ता का अहंकार कभी स्थायी नहीं होता, लेकिन लोकतंत्र और संविधान हमेशा सर्वोपरि रहेंगे। उन्होंने जंतर-मंतर की इस कार्रवाई की कड़े शब्दों में निंदा की और केंद्र सरकार से मांग कि छात्रों की आवाज़ को दबाने के बजाय उनकी बात सुनी जाए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाये और छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों का सम्मान सुनिश्चित किया जाए। याद रखिए, युवाओं की आवाज़ को दबाया जा सकता है, हराया नहीं जा सकता । लोकतंत्र में लाठी नहीं, संवाद होना चाहिए।

मौसमी बीमारियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु जिले में नियमित रूप से एंटीलार्वा गतिविधियों का संचालन

जयपुर। मानसून में मच्छरों के प्रजनन की संभावना बढ़ने के मद्देनज़र जिले में मौसमी बीमारियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु नियमित रूप से एंटीलार्वा गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम डॉ. रवि शेखावत एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय डॉ. मनीष मित्तल ने बताया कि मौसमी बीमारियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चिकित्साकर्मियों द्वारा निरंतर सोर्स रिडक्शन, एन्टीअडल्ट व जागरूकता के लिए आईईसी की गतिविधियाँ आयोजित की जा रही हैं। इस दौरान आमजन को मौसमी बीमारियों के प्रति जागरूक किया जा रहा है तथा जिला व ब्लॉक स्तर से मोनिटरिंग और सुपरविजन किया जा रहा है। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि वे मौसमी बीमारियों पर नियंत्रण हेतु सक्रिय सहयोग करें तथा अपने घर, कार्यस्थल और आसपास स्वच्छता बनाए रखते हुए कहीं भी पानी का ठहराव न होने दें। जनभागीदारी से ही रोग मुक्त एवं स्वस्थ समाज का निर्माण संभव है। उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, स्वास्थ्य जयपुर प्रथम डॉ. इंद्रा गुप्ता और उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, स्वास्थ्य जयपुर द्वितीय डॉ. सुरेन्द्र कुमार गोयल ने बताया कि मौसमी बीमारियों पर नियंत्रण के लिए एंटीलार्वा, सर्वे, सैम्पलिंग सहित विभिन्न जागरुकता गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। मौसमी बीमारियों से बचाव हेतु एहतियात बरतनी जरूरी हैं। बीमारियों पर अंकुश लगाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी मच्छरों को पनपने से रोकना है। इसके लिए आस-पास पर्याप्त साफ-सफाई पर ध्यान देना बेहद आवश्यक है। सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें। बुखार होने पर बिना देरी किए चिकित्सक से मिले और उपचार लेवें।

चेक अनादरण प्रकरण में अभियुक्त दोषी, 6 माह का कारावास व 90 हजार क्षतिपूर्ति का आदेश

परिवादी की ओर से सीनियर एडवोकेट अशोक जी अरोड़ा ने अपने सहयोगी अधिवक्ता मोहम्मद शरीफ के साथ प्रभावी पैरवी की

अतुल्य संसार नेटवर्क

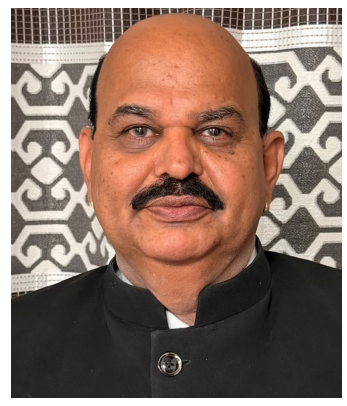

पाली। न्यायालय विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट प्रकरण संख्या-2), पाली की पीठासीन अधिकारी विनस जी चौधरी (आर.जे.एस.) ने चेक अनादरण के एक महत्वपूर्ण प्रकरण परिवादी जय राज टैक्स बनाम अभियुक्त बृज किशोर मुकदमा संख्या 695/2020 में अभियुक्त बृज किशोर त्रिपाटी पुत्र श्याम किशोर त्रिपाटी निवासी राइकों की ढाणी पाली को परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अंतर्गत दोषी ठहराते हुए 6 माह के साधारण कारावास तथा 90,000 क्षतिपूर्ति परिवादी को अदा करने का आदेश दिया।

परिवादी राजमल कवाड पुत्र विजय राज प्रोपराइटर जय राज टैक्स ई 28 मंडिया रोड पाली ने परिवाद प्रस्तुत कर बताया कि अभियुक्त उसकी फैक्ट्री में लेबर के रूप में कार्य करता था। घरेलू आवश्यकता बताकर अभियुक्त ने एक बार 60,000 तथा दूसरी बार 1,50,000 का ऋण चेक के माध्यम से लिया था। बाद में 1,50,000 की राशि लौटा दी, जबकि 60,000 के बकाया भुगतान के लिए दिया गया चेक बैंक में प्रस्तुत करने पर खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण अनादरित हो गया। इसके बाद विधिक नोटिस भेजा गया, किंतु नोटिस की तामील के बावजूद अभियुक्त ने भुगतान नहीं किया।

अभियुक्त ने अपने बचाव में कहा कि वह परिवादी की फर्म में नौकरी करता था वेतन बढ़ाने का कहने से परिवादी नाराज हो गया, नौकरी ज्वाइन करने से पहले परिवादी ने उसका बैंक खाता खुलवा कर चेक बुक अपने पास रख ली थी। वेतन भी समय पर नहीं देता था।वेतन को लेकर बोल चाल होने पर नौकरी से निकाल दिया, और चेक बुक अपने पास रख ली और चेक बुक में से चेक का दुरुपयोग कर झूठा मुकदमा किया है परिवादी मुझसे कोई रुपए नहीं मांगता है बल्कि परिवादी से मैं मेरा बकाया वेतन फरवरी 2019 से सितंबर 2019 का मांगता हूं जो वो नहीं दे रहा है और मेरा बकाया वेतन नहीं देना पड़े इस नियत से यह झूठा मुकदमा किया है। नौकरी छोड़ने के बाद दस बार बकाया वेतन और खाली लिए गए चेक मांगने गया परंतु नहीं दिए।

उसने उधार लिए 60 हजार रुपए भी किस्तों में चुका दिए। ये चेक जब परिवादी ने उसे नौकरी पर रखा था तब उससे खाली हस्ताक्षर करवा कर जमानत और सिक्यूरिटी पेटे लिया था,उसकी सेलेरी जो बकाया है जो परिवादी देना नहीं चाहता है और वह कलर मास्टर है परिवादी उसे अपने यहां से जाने देना नहीं चाहता था जबरदस्ती रोक कर रखना चाहता था तो उसने सेलरी बढ़ाने का कहा जिस पर विवाद हुआ और नौकरी से निकाल दिया जमानत पेटे लिए गए चेक भी मांगने पर नहीं लौटाये और उनका दुरुपयोग कर झूठा मुकदमा किया है।

न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि अभियुक्त ने यह स्वीकार किया कि विवादित चेक उसके बैंक खाते का है, उस पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा चेक उसी ने परिवादी को दिया था। ऐसी स्थिति में कानून के अनुसार यह उपधारणा लागू होती है कि चेक वैध देयता के निर्वहन हेतु जारी किया गया था। न्यायालय ने पाया कि अभियुक्त अपने बचाव के समर्थन में न तो चेक के कथित दुरुपयोग संबंधी कोई कार्यवाही का प्रमाण प्रस्तुत कर सका और न ही बकाया वेतन के संबंध में कोई दस्तावेज अथवा वसूली की कार्यवाही का रिकॉर्ड पेश कर पाया। फलस्वरूप अभियुक्त वैधानिक उपधारणा का खंडन करने में असफल रहा, जबकि परिवादी अपना मामला संदेह से परे सिद्ध करने में सफल रहा।

इसी आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को धारा 138 एन.आई. एक्ट के तहत दोषसिद्ध घोषित करते हुए 6 माह के साधारण कारावास तथा ?90,000 क्षतिपूर्ति अदा करने का आदेश पारित किया।

प्रकरण में परिवादी की ओर से सीनियर एडवोकेट अशोक अरोड़ा ने अपने सहयोगी अधिवक्ता मोहम्मद शरीफ के साथ प्रभावी पैरवी की।

शिक्षा व्यवस्था छोड़ निजी स्कूलों पर क्यों मेहरबान हैं शिक्षा मंत्री? अभिभावकों के प्रति जवाबदेही कब होगीः संयुक्त अभिभावक संघ

अतुल्य संसार नेटवर्क

जयपुर। निजी स्कूलों की मान्यता संबंधी आवेदनों में देरी करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करने संबंधी शिक्षा मंत्री की घोषणा पर संयुक्त अभिभावक संघ ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि यदि सरकार निजी स्कूल संचालकों के मामलों में समयबद्ध जवाबदेही तय कर सकती है, तो आखिर प्रदेश के करोड़ों अभिभावकों की शिकायतों पर ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं बनाई जा रही?

संयुक्त अभिभावक संघ के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक जैन बिट्टू ने कहा कि शिक्षा मंत्री का यह रवैया स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि सरकार निजी स्कूल संचालकों की परेशानियों को लेकर तो गंभीर है, लेकिन वर्षों से शिक्षा विभाग और निजी स्कूलों की मनमानी का सामना कर रहे अभिभावकों की पीड़ा से पूरी तरह उदासीन बनी हुई है। उन्होंने कहा कि आज आरटीई प्रवेश प्रक्रिया की लॉटरी जारी हुए लगभग 140 दिन बीत चुके हैं, लेकिन लाखों अभिभावक आज भी शिक्षा विभाग के कार्यालयों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। शिक्षा विभाग शिकायतों का समाधान करने के बजाय अभिभावकों को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय भेजकर केवल ठोकरें खिलाने का काम कर रहा है। यदि निजी स्कूलों की मान्यता के मामलों में समयबद्ध कार्रवाई की व्यवस्था बनाई जा सकती है, तो क्या शिक्षा मंत्री यही व्यवस्था अभिभावकों की शिकायतों के लिए भी लागू करेंगे? अभिषेक जैन बिट्टू ने कहा कि संयुक्त अभिभावक संघ को निजी स्कूलों को समय पर मान्यता मिलने या उनकी प्रशासनिक समस्याओं के समाधान पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सरकार का यह दोहरा रवैया स्वीकार्य नहीं है। एक ओर निजी स्कूल संचालकों के हितों की रक्षा के लिए तत्काल समीक्षा बैठकें होती हैं, दूसरी ओर अभिभावकों की शिकायतें महीनों तक फाइलों में दबी रहती हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के अभिभावक आज भी अनेक गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं-

* आरटीई के तहत चयनित बच्चों को समय पर प्रवेश नहीं मिल रहा।

* निजी स्कूल मनमानी फीस वसूल रहे हैं।

* निर्धारित दुकानों से महंगी ड्रेस और किताबें खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है।

* बच्चों के भविष्य और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में भी विभाग की ओर से प्रभावी कार्रवाई नहीं होती।

* सरकारी स्कूलों की अव्यवस्थाओं और निजी स्कूलों की मनमानी के विरुद्ध दर्ज शिकायतों पर कोई समयबद्ध जवाबदेही तय नहीं है।

संयुक्त अभिभावक संघ ने शिक्षा मंत्री से सवाल किया है कि यदि अधिकारियों पर कार्रवाई की चेतावनी केवल निजी स्कूलों की मान्यता संबंधी मामलों तक सीमित रहेगी, तो फिर प्रदेश के करोड़ों अभिभावकों के अधिकारों की रक्षा कौन करेगा? क्या अभिभावक इस सरकार की प्राथमिकता में शामिल नहीं हैं? संघ ने मांग की है कि जैसे निजी स्कूलों के आवेदनों के निस्तारण के लिए समयसीमा तय की जा रही है, उसी प्रकार अभिभावकों की सभी शिकायतों-आरटीई प्रवेश, मनमानी फीस, ड्रेस, किताबें, विद्यालयों की मनमानी तथा सरकारी स्कूलों की लापरवाही-के लिए भी समयबद्ध जवाबदेही कानूनन सुनिश्चित की जाए। शिकायतों के निराकरण में देरी करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध भी समान रूप से कार्रवाई की जाए। अभिषेक जैन बिट्टू ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य निजी संस्थानों को संरक्षण देना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों और अभिभावकों के अधिकारों की रक्षा करना होना चाहिए। यदि सरकार वास्तव में शिक्षा सुधार के प्रति गंभीर है, तो उसे सबसे पहले उन करोड़ों अभिभावकों की आवाज सुननी होगी, जो वर्षों से शिक्षा विभाग और निजी स्कूलों की मनमानी के बीच न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

लोहार्गल में मूसलाधार बारिश से उफान पर 'ताक झरना', तेज बहाव में बहीं तीन बाइकें

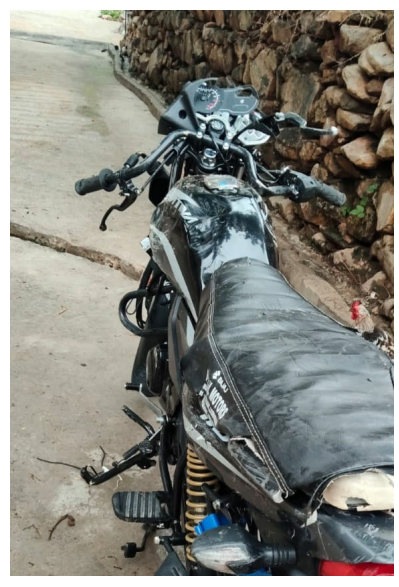

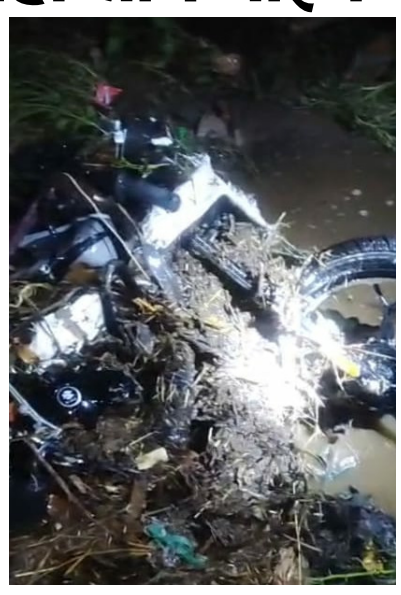

सुमेर सिंह राव/उदयपुरवाटी / चिराना/लोहार्गल। क्षेत्र में मौसम ने अचानक करवट बदली है। सोमवार देर रात से शुरू हुआ झमाझम बारिश का दौर मंगलवार सुबह तक जारी रहा। इस मूसलाधार बरसात से जहां आमजन को भीषण गर्मी और उमस से बड़ी राहत मिली है, वहीं नदी-नाले और पहाड़ी झरने पूरे वेग से बहने लगे हैं।

500 मीटर दूर मलबे में मिलीं मोटरसाइकिलें

भारी बारिश के चलते प्रसिद्ध तीर्थ स्थल लोहार्गल का ताक झरना रौद्र रूप में आ गया। झरने के पास स्थित एक मकान के बाहर खड़ी तीन मोटरसाइकिलें पानी के तेज बहाव की चपेट में आ गईं। बहाव इतना भयंकर था कि तीनों बाइकें ताश के पत्तों की तरह बहती हुई करीब 500 मीटर दूर जा गिरीं। पानी उतरने के बाद ये बाइकें बेहद जर्जर और क्षतिग्रस्त हालत में मलबे के बीच दबी मिलीं। पीड़ित शोएब पुत्र दांखु खां ने बताया कि रात को अचानक पानी का स्तर बढ़ने से गाड़ियों को निकालने का मौका ही नहीं मिला।

पर्यटकों की बढ़ी आमद, ग्रामीणों ने की पुलिस सुरक्षा की मांग

पहाड़ों पर झरने चलने की खबर फैलते ही लोहार्गल में पर्यटकों और स्थानीय सैलानियों की भारी भीड़ जुटने लगी है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर स्थानीय ग्रामीण चिंतित हैं। ग्रामीणों का कहना है कि भीड़ बढ़ने के साथ ही हुड़दंग मचाने वाले असामाजिक तत्वों की गतिविधियां भी बढ़ जाती हैं, जिससे हादसों का खतरा बना रहता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने और ताक झरने के पास तुरंत पुलिस बल तैनात करने की पुरजोर मांग की है।

मौसम विभाग का 5 दिनों का अलर्ट, रहें सावधान

मौसम विभाग ने क्षेत्र में आगामी चार से पांच दिनों तक मौसम खराब रहने और भारी बारिश का अलर्ट (**Alert**) जारी किया है। प्रशासन ने भी पहाड़ी क्षेत्रों और झरनों के आस-पास रहने वाले लोगों तथा पर्यटकों से सावधानी बरतने और तेज बहाव वाले रास्तों से दूर रहने की अपील की है।

शिक्षा व्यवस्था छोड़ निजी स्कूलों पर क्यों मेहरबान हैं शिक्षा मंत्री? अभिभावकों के प्रति जवाबदेही कब होगीः संयुक्त अभिभावक संघ

अतुल्य संसार नेटवर्क

जयपुर। निजी स्कूलों की मान्यता संबंधी आवेदनों में देरी करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करने संबंधी शिक्षा मंत्री की घोषणा पर संयुक्त अभिभावक संघ ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि यदि सरकार निजी स्कूल संचालकों के मामलों में समयबद्ध जवाबदेही तय कर सकती है, तो आखिर प्रदेश के करोड़ों अभिभावकों की शिकायतों पर ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं बनाई जा रही? संयुक्त अभिभावक संघ के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक जैन बिट्टू ने कहा कि शिक्षा मंत्री का यह रवैया स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि सरकार निजी स्कूल संचालकों की परेशानियों को लेकर तो गंभीर है, लेकिन वर्षों से शिक्षा विभाग और निजी स्कूलों की मनमानी का सामना कर रहे अभिभावकों की पीड़ा से पूरी तरह उदासीन बनी हुई है। उन्होंने कहा कि आज आरटीई प्रवेश प्रक्रिया की लॉटरी जारी हुए लगभग 140 दिन बीत चुके हैं, लेकिन लाखों अभिभावक आज भी शिक्षा विभाग के कार्यालयों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। शिक्षा विभाग शिकायतों का समाधान करने के बजाय अभिभावकों को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय भेजकर केवल ठोकरें खिलाने का काम कर रहा है। यदि निजी स्कूलों की मान्यता के मामलों में समयबद्ध कार्रवाई की व्यवस्था बनाई जा सकती है, तो क्या शिक्षा मंत्री यही व्यवस्था अभिभावकों की शिकायतों के लिए भी लागू करेंगे?

अभिषेक जैन बिट्टू ने कहा कि संयुक्त अभिभावक संघ को निजी स्कूलों को समय पर मान्यता मिलने या उनकी प्रशासनिक समस्याओं के समाधान पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सरकार का यह दोहरा रवैया स्वीकार्य नहीं है। एक ओर निजी स्कूल संचालकों के हितों की रक्षा के लिए तत्काल समीक्षा बैठकें होती हैं, दूसरी ओर अभिभावकों की शिकायतें महीनों तक फाइलों में दबी रहती हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के अभिभावक आज भी अनेक गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं-

* आरटीई के तहत चयनित बच्चों को समय पर प्रवेश नहीं मिल रहा। * निजी स्कूल मनमानी फीस वसूल रहे हैं।

* निर्धारित दुकानों से महंगी ड्रेस और किताबें खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है।

* बच्चों के भविष्य और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में भी विभाग की ओर से प्रभावी कार्रवाई नहीं होती।

* सरकारी स्कूलों की अव्यवस्थाओं और निजी स्कूलों की मनमानी के विरुद्ध दर्ज शिकायतों पर कोई समयबद्ध जवाबदेही तय नहीं है। संयुक्त अभिभावक संघ ने शिक्षा मंत्री से सवाल किया है कि यदि अधिकारियों पर कार्रवाई की चेतावनी केवल निजी स्कूलों की मान्यता संबंधी मामलों तक सीमित रहेगी, तो फिर प्रदेश के करोड़ों अभिभावकों के अधिकारों की रक्षा कौन करेगा? क्या अभिभावक इस सरकार की प्राथमिकता में शामिल नहीं हैं?

संघ ने मांग की है कि जैसे निजी स्कूलों के आवेदनों के निस्तारण के लिए समयसीमा तय की जा रही है, उसी प्रकार अभिभावकों की सभी शिकायतों-आरटीई प्रवेश, मनमानी फीस, ड्रेस, किताबें, विद्यालयों की मनमानी तथा सरकारी स्कूलों की लापरवाही-के लिए भी समयबद्ध जवाबदेही कानूनन सुनिश्चित की जाए। शिकायतों के निराकरण में देरी करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध भी समान रूप से कार्रवाई की जाए। अभिषेक जैन बिट्टू ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य निजी संस्थानों को संरक्षण देना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों और अभिभावकों के अधिकारों की रक्षा करना होना चाहिए। यदि सरकार वास्तव में शिक्षा सुधार के प्रति गंभीर है, तो उसे सबसे पहले उन करोड़ों अभिभावकों की आवाज सुननी होगी, जो वर्षों से शिक्षा विभाग और निजी स्कूलों की मनमानी के बीच न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

डीग जिले के सभी न्यायाधीशगण के द्वारा विद्यालयों के बच्चों को नशे से दूर रहने से संबंधित जानकारियां प्रदान की

दीपचंद शर्मा डीग। माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (रालसा), जयपुर के तत्वाधान एवं निर्देशानुसार आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , डीग द्वारा ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूसडे (Transforming Tuesday) अभियान के अंतर्गत जिले के विभिन्न विद्यालयों में विधिक जागरूकता शिविरों का गरिमामय आयोजन किया गया। इस माह के तीसरे मंगलवार (21 जुलाई 2026) को आयोजित इन शिविरों की मुख्य थीम नशे को ना कहो, अपने सपनों को हाँ कहो – नशा कोई स्टाइल नहीं है, अपने मन, शरीर और भविष्य की रक्षा करो रही। विभिन्न विद्यालयों में आयोजित विधिक जागरूकता शिविर- महात्मा गांधी राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल,डीग- जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री हेमराज गौड़ जी तथा सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री राम किशन शर्मा जी के नेतृत्व में शिविर का आयोजन किया गया। माननीय न्यायाधीशों ने विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति सचेत करते हुए जीवन में एक नई दिशा चुनने का संदेश दिया और अपने मन, शरीर एवं भविष्य की रक्षा करने का आह्वान किया इस मौके पर लीगल डिफेंस काउंसिल के डिप्टी चीफ राजेंद्र शर्मा उपस्थित रहे । राजकीय माध्यमिक विद्यालय दिदावली (डीग)- माननीय प्रधान मजिस्ट्रेट (जे.जे.बी. बोर्ड) श्रीमती कुसुम मीणा द्वारा राजकीय माध्यमिक विद्यालय, ददावली में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया।

इस दौरान बच्चों को नशे से दूर रहने एवं इसके दुष्परिणामों के संबंध में विस्तार से बेहतर और उपयोगी जानकारी दी गई।

प्रेम भारती बीपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, डीग: अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्रीमती सरोज मीणा की अध्यक्षता में जागरूकता कार्यक्रम संपन्न हुआ। उन्होंने विद्यार्थियों को नशे से दूर रहकर अपने उज्ज्वल भविष्य के निर्माण के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर लीगल डिफेंस काउंसिल के चीफ विनोद कुमार शर्मा उपस्थित रहे । राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय निगोही एवं बंधा- अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) श्री नमो नारायण मीणा द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय निगोही एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बंडा में शिविरों का आयोजन कर बच्चों को नशे से दूर रहने तथा सही राह चुनने का संदेश दिया गया। **न्यायाधीशों का साझा संदेश:** सभी माननीय न्यायाधीशों ने एक स्वर में स्कूल के बच्चों को नशे से दूर रहने की हिदायत दी और उन्हें जीवन में सही मार्ग पर चलने के लिए एक नई दिशा प्रदान की। उन्होंने स्पष्ट किया कि नशा कोई स्टाइल नहीं है, इसलिए अपनी ऊर्जा और ध्यान को अपने सपनों को पूरा करने तथा भविष्य को सुरक्षित बनाने में लगाएं। आयोजित शिविरों में विद्यालयों के संस्थाप्रधान, शिक्षकगण, पैरा लीगल वॉलंटियर्स (PLVs) एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

दिल्ली के संसद घेराव में बरसे गैस के गोलों से आदिवासी नेता सुरेश मीणा किशोरपुरा की तबीयत खराब

2 दिन बाद भी आंखों पर जाला अस्पताल में भर्ती होने की सलाह

जंतर-मंतर पर हो गए थे एक बार के लिए अचेत

● अतुल्य संसार नेटवर्क

चंवरा। नीट स्टूडेंट प्रदीप मेघवाल प्रकरण में निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर उदयपुरवाटी उपखंड क्षेत्र से उनके परिजनों के साथ मीन सेना के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश मीणा किशोरपुरा और रवींद्र सिंह पौंख ने भी दिल्ली में जंतर-मंतर पर आयोजित संसद घेराव में शामिल हुए थे। सोमवार को प्रदर्शनकारी जंतर मंतर से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को लेकर संसद तक मार्च कर रहे थे तभी छात्र-छात्राओं और अभिभावकों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज और आंसू गैस के गोले दागे गए। जिसकी चपेट में आने से आदिवासी नेता सुरेश मीणा किशोरपुरा की तबीयत बिगड़ गई। उनके दो दिन बाद भी आंखों पर जाला फिरा हुआ है। वहीं स्वांस लेने में भी हल्की दिक्कत महसूस हो रही है। ऐसे में स्थानीय डॉक्टरों ने उन्हें आंखों के अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी है। हालांकि सुरेश मीणा किशोरपुरा ने कहा कि अफवाहों से सावधान रहें मेरे ज्यादा कोई तकलीफ नहीं है। आंसू गैस के गोलों की चपेट में आने से मेरी आंखें अच्छे ढंग से खुल नहीं रही हैं और थोड़ी स्वांस लेने में भी दिक्कत है। आंखों में जलन है दिल और दिमाग में भी बेचैनी है। बुधवार को जयपुर में अच्छे चिकित्सक से इलाज लेंगे।

भाजपा जयपुर शहर कार्यालय में श्रद्धा एवं भक्ति के साथ हुआ मासिक सुंदरकांड पाठ

● अतुल्य संसार नेटवर्क

जयपुर। भारतीय जनता पार्टी जयपुर शहर कार्यालय में मंगलवार को मासिक सुंदरकांड पाठ का आयोजन श्रद्धा एवं भक्तिभाव के साथ किया गया। जिसमें बड़ी संख्या में पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। महाआरती के उपरांत सभी भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया। जिला अध्यक्ष अमित गोयल ने कहा कि धर्म और समाज, राजनीति को सकारात्मक दिशा देने के सशक्त माध्यम हैं। ऐसे धार्मिक आयोजनों से संगठन में एकता, सेवा, संस्कार और राष्ट्रहित की भावना सुदृढ़ होती है। कार्यक्रम में भगवान श्रीराम एवं श्रीहनुमान जी की आराधना के साथ सुंदरकांड का सामूहिक पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, भजन-कीर्तन एवं महाआरती का आयोजन हुआ। पूरे वातावरण में भक्तिमय उल्लास और जय श्रीराम के उद्घोष गूंजते रहे। इस अवसर पर भाजपा जयपुर के महामंत्री राजेश ताम्बी, रेखा राठौड़, नवरत्न नाराणिया सहित जयपुर शहर के समस्त पदाधिकारी, विभिन्न मंडलों के कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में महिलाएं एवं श्रद्धालु उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान बना खनन का सिरमौर

विगत ढाई वर्ष में प्रदेशभर में 102 मिनरल ब्लॉक की हुई नीलामी

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान खनन क्षेत्र का सिरमौर बन कर उभर रहा है। प्रधान खनिजों के 141 खनिज ब्लॉकों की ई-नीलामी के साथ राजस्थान ने प्रधान खनिजों की नीलामी में देशभर में पहला स्थान हासिल किया है। मुख्यमंत्री के निर्देशों की अनुपालना में खनिज खोज और खनिज ब्लॉकों के योजनाबद्ध नीलामी की प्रभावी कार्ययोजना तैयार की गई। जिसके परिणामस्वरूप राजस्थान के खान विभाग ने मेजर मिनरल ब्लॉकों की ई-नीलामी में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। चालू वित्तीय वर्ष के भी आरंभिक तीन-साडे तीन माह में ही 14 प्रधान खनिज ब्लॉकों की ई-नीलामी की जा चुकी है। खनन विभाग ने इस वित्तीय वर्ष में 55 प्रधान खनिज ब्लॉकों की नीलामी की कार्ययोजना तैयार कर क्रियान्वयन शुरु किया है।

राजस्थान ने खनन क्षेत्र में रचा कीर्तिमान

राज्य सरकार ने विगत ढाई वर्षों में 102 प्रधान खनिज ब्लॉकों की ई-नीलामी की है जबकि इससे पहले नई व्यवस्था लागू होने से लेकर 14 दिसंबर, 2023 तक केवल 39 प्रधान खनिज ब्लॉकों की ही नीलामी हुई थी। मुख्यमंत्री के निर्देशन में वर्ष 2024-25 में 34 ब्लॉकों, वर्ष 2025-26 में 39 प्रधान खनिज ब्लॉकों की ई-नीलामी की गई है।

सघन एवं नियमित मॉनिटरिंग से खनिज खोज को मिल रही गति

खान एवं भूविज्ञान विभाग द्वारा खनिज खोज से लेकर ई-नीलामी के लिए सघन एवं नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है। इससे प्रदेश में खनिज खोज और ई-ऑक्शन प्रक्रिया को गति मिल रही है। विभाग में पोस्ट ऑक्शन फेसिलिटेशन सेल गठित कर नीलाम ब्लॉकों को पर्यावरण स्वीकृति सहित आवश्यक अनुमतियां दिलाने में समन्वय व सहयोग किया जा रहा है।

ई-नीलामी प्रक्रिया से बदल रही प्रदेश में खनन की तस्वीर

खान एवं भूविज्ञान विभाग द्वारा ई-नीलाम किये गये 141 प्रधान खनिज ब्लॉकों में से 105 खनिज ब्लॉकों की माइनिंग लीज और 30 खनिज ब्लॉकों की कंपोजिट लाइसेंस के लिए नीलामी की गई है। इसके अलावा एक एक्सप्लोरेशन लाइसेंस के लिए नीलामी की गई है। सामरिक महत्व को देखते हुए इनमें से राजस्थान से ही 7 क्रिटिकल एवं स्ट्रेटेजिक मिनरल ब्लॉकों की नीलामी भारत सरकार द्वारा की गई है। राज्य में ई-नीलामी प्रक्रिया लागू होने के बाद से अब तक सर्वाधिक 101 लाइमस्टोन के ब्लॉकों की नीलामी हुई है। इसके अलावा आयरन ओर के 13, बेसमेटल के 8, सिलियस अर्थ के 4, मैगनिज के 3, गोल्ड के 2, पोटाश एवं हैलाइट के 2, रेयर अर्थ एलिमेंट के 4 और गार्नेट, एमरल्ड, फ्लोराइट व रॉक फास्फेट के एक-एक ब्लॉकों की नीलामी हुई है। विभाग का फोकस नीलाम ब्लॉकों को परिचालन में लाने पर है।

विप्र फाउंडेशन ने ईडब्ल्यूएस के राजनीतिक प्रतिनिधित्व एवं आयोग गठन की मांग को लेकर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

● अतुल्य संसार नेटवर्क

झुंझुनूं/अरुण कुमार। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के अधिकारों की रक्षा तथा पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनावों में राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की मांग को लेकर विप्र फाउंडेशन के संयोजन में जिला प्रशासन के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन विप्र फाउंडेशन जिला अध्यक्ष कमलकांत शर्मा एवं गौड़ ब्राह्मण महासभा के कार्यकारी अध्यक्ष प्रदीप शर्मा (अलसीसर) के नेतृत्व में प्रस्तुत किया गया।

ज्ञापन में मांग की गई है कि आगामी पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनावों में ईडब्ल्यूएस वर्ग को भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के लिए आवश्यक प्रावधान किए जाएं, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रभावी भागीदारी निभा सके। साथ ही यह भी मांग की गई कि जिस प्रकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सीटों पर अन्य वर्ग चुनाव नहीं लड़ सकते, उसी प्रकार ईडब्ल्यूएस वर्ग के हितों की रक्षा के लिए भी उपयुक्त व्यवस्था लागू की जाए, जिससे इस वर्ग को संविधान प्रदत्त आरक्षण का वास्तविक लाभ मिल सके।

ज्ञापन में राज्य स्तर पर ईडब्ल्यूएस आयोग के गठन की भी मांग की गई। आयोग आय सीमा, पात्रता, प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया तथा ईडब्ल्यूएस से जुड़े सभी नियमों की नियमित समीक्षा कर व्यावहारिक कमियों को दूर करे तथा यह सुनिश्चित करे कि पात्र परिवारों को योजनाओं एवं आरक्षण का लाभ बिना किसी अनावश्यक बाधा के प्राप्त हो।

प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि ईडब्ल्यूएस वर्ग से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण विषय लंबे समय से लंबित हैं। सरकार को इन मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार कर शीघ्र निर्णय लेना चाहिए, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के संवैधानिक अधिकारों की प्रभावी रक्षा हो सके।

जिला संयोजक उमाशंकर महमिया एवं जिला संगठन महामंत्री रामगोपाल महमिया ने बताया कि यदि सरकार द्वारा ईडब्ल्यूएस वर्ग को उसका संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित किए बिना पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव कराए जाते हैं, तो इस संबंध में राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ में रिट याचिका दायर की जाएगी। उन्होंने कहा कि ईडब्ल्यूएस वर्ग के अधिकारों की अनदेखी कर चुनाव कराना न्यायोचित नहीं होगा। ज्ञापन के माध्यम से सरकार का ध्यान ईडब्ल्यूएस वर्ग की प्रमुख समस्याओं एवं मांगों की ओर आकर्षित करते हुए दोनों मांगों पर शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई की अपेक्षा व्यक्त की गई।

ज्ञापन सौंपने के दौरान संरक्षक राजेंद्र जोशी, एडवोकेट सुशील जोशी, जिला महामंत्री वशिष्ठ शर्मा, राकेश शर्मा बगड़, नरेंद्र व्यास, जिला कोषाध्यक्ष राकेश सहल,महिला जिलाध्यक्ष ममता शर्मा, मंत्री एडवोकेट नीरज शर्मा, रमेश चौमाल, महावीर भेड़ा गुड्डा, गुरुदयाल शर्मा (बुहाना), एडवोकेट मनोज शर्मा, तहसील अध्यक्ष अनिल जोशी, रामगोपाल शर्मा (बीएमएस), श्यामसुंदर दाधीच, एडवोकेट अनुपम शर्मा, एडवोकेट अंजू शर्मा, ललित शर्मा, डब्ल्यू शर्मा, प्रमोद चोटिया, राजदीप महर्षि, विकास पुरोहित, सुभाष जोशी, एडवोकेट पंकज शर्मा बावलिया , संजय शुक्ला, एडवोकेट कैलाश शर्मा, एडवोकेट कमल शर्मा, संजय शर्मा लूमास सहित विप्र फाउंडेशन के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

मुंबई के ऋषिकेश तुलसियन ने सिंगापुर में जीते 3 सिल्वर मेडल, 40 देशों में लहराया परचम

झुंझुनू का लाडला बेटा है ऋषिकेश

सुमेर सिंह राव/झुंझुनू / मुंबई/सिंगापुर। मुंबई स्थित डॉन-बॉस्को इंटरनेशनल हाई स्कूल के 7वीं कक्षा के छात्र ऋषिकेश अभिनंदन तुलसियन ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का नाम रोशन किया है। सिंगापुर में आयोजित प्रतिष्ठित सिंगापुर इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड चैलेंज (SIMOC) 2026 में ऋषिकेश ने 3 सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। यह प्रतियोगिता केवल आमंत्रण-आधारित थी, जिसमें दुनिया के 40 देशों और क्षेत्रों के 2,285 टॉप प्रदर्शन करने वाले छात्रों ने हिस्सा लिया था। छात्रों को तीन कठिन चरणों में परखा गया – एक व्यक्तिगत लिखित मैथ ओलंपियाड और दो टीम-आधारित इवेंट्स मैथ्स वॉरियर्स और *मैथ मास्टर माइंड*।

ऋषिकेश ने तीनों ही इवेंट्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम किए।छोटी बहन ने भी किया कमाल तीसरी कक्षा की वेदांशिका तुलसियन ने जीते 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल प्रतिभा इस परिवार में कूट-कूट कर भरी है। ऋषिकेश की छोटी बहन, डॉन-बॉस्को इंटरनेशनल हाई स्कूल की तीसरी कक्षा की छात्रा वेदांशिका अभिनंदन तुलसियन ने भी SIMOC 2026 में शानदार सफलता हासिल की है। वेदांशिका ने व्यक्तिगत लिखित मैथ ओलंपियाड में सिल्वर और टीम इवेंट मैथ्स वॉरियर्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इतनी छोटी उम्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दो मेडल जीतना उनकी असाधारण गणितीय प्रतिभा को दर्शाता है। दोनों भाई-बहन की इस दोहरी सफलता पर स्कूल प्रबंधन और परिवार में हर्ष का माहौल है।

'जो सरकार बच्चों की नहीं हो सकी वो किसी की भी नहीं हो सकतीः छात्र आंदोलन से बौखलाई मोदी सरकार - राखी गौतम'

● अतुल्य संसार नेटवर्क

पूछने वाले युवा सड़कों पर लाठियां खा रहे हैं।

कोटा। शहर जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष राखी गौतम ने कल दिल्ली के जंतर-मंतर पर अपने अधिकारों और न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्र-छात्राओं पर किए गए लाठीचार्ज को बेहद निंदनीय बताया है। राखी गौतम ने कहा कि बच्चों पर जुल्म करना लोकतंत्र नहीं, तानाशाही है। लोकतंत्र में आवाज़ दबाने के लिए लाठियाँ नहीं, संवाद का रास्ता अपनाया जाता है। युवाओं के सवालों का जवाब बल प्रयोग से नहीं, न्याय और पारदर्शिता से दिया जाना चाहिए। याद रखिए, जब युवाओं का धैर्य टूटता है तो वही जनआक्रोश सत्ता के लिए सबसे बड़ा संदेश बन जाता है। गौतम ने कहा कि पेपर लीक कराने वाले सत्ता में सुरक्षित हैं और सवाल BJP का यही नया लोकतंत्र है! जंतर-मंतर पर युवाओं पर किया गया लाठीचार्ज मोदी सरकार की दमनकारी सोच और कायरता का सबूत है।

गौतम ने कहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर मौन साधे बैठी सरकार भूल रही है कि लाठियां बरसा कर युवाओं की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। जो सरकार बच्चों की नहीं हो सकी तो वह किसी की भी नहीं हो सकती। सरकार को समझना ही होगा कि आज का युवा अंदर से कितना पीड़ित और परेशान है। जब इतने बड़े स्तर पर छात्र सड़क पर हैं, तो सिस्टम की जवाबदेही तय होनी ही चाहिए। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि लाठीचार्ज के दोषियों पर कार्रवाई हो और शिक्षा मंत्री तुरंत इस्तीफा दें।

मकराना में बंजारा एकता संकल्प यात्रा का भव्य स्वागत

● अतुल्य संसार नेटवर्क

मकराना। आंध्र प्रदेश के सेवागढ़ से प्रारंभ हुई बंजारा एकता संकल्प यात्रा का मकराना पहुंचने पर बंजारा समाज एवं स्थानीय लोगों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। लगभग 7,000 किलोमीटर की यात्रा तय कर यह संकल्प यात्रा 27 जुलाई को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम पहुंचेगी। मकराना के यात्रा भाटीपुरा सूरजपाल बड़त्या के आवास पहुंचने पर समाजबंधुओं द्वारा पुष्पवर्षा, डीजे एवं रैली के माध्यम से यात्रियों का स्वागत किया गया। इस अवसर पर पूज्य श्री जी महाराज सेवागढ़ पुजारी, बाबूसिंह राठौड़ पोहरा देवी धर्म गुरु ने समाज की एकता बनाए रखने का आह्वान किया, वहीं नांदेड़ से सरदार राजा सिंह राठौर ने सिख धर्म गुरु और बंजारा समाज के बारे में जानकारी दी। यात्रा में शामिल सभी समाजबंधुओं का स्वागत किया गया। पूज्य महाराज जी को मार्बल की प्रतिमा भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम मे धर्म गुरु जी ने बंजारा समाज की एकता, इतिहास, संस्कृति एवं सामाजिक संघर्ष पर विस्तृत चर्चा कर बंजारा समाज में शिक्षा पर ध्यान देना होगा तभी समाज आगे बढ़ेगा साथ ही संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी दी तथा समाज की एकता और संघर्ष की आवश्यकता पर विचार व्यक्त किए। अखिल भारतीय बंजारा सेवा संघ प्रदेश अध्यक्ष सूरजपाल बड़त्या ने समाजबंधुओं से 27 जुलाई को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम पहुंचने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यह संकल्प यात्रा बंजारा समाज की एकता, इतिहास, संस्कृति और सामाजिक जागरूकता का प्रतीक है। रैली का संचालन ईश्वर बिजरावत एवं सूरजपाल बडत्या ने किया। कार्यक्रम में कांतिलाल नाइक,विलास रामावत,सरदार राजा सिंह,किशोर नाइक, कल्याण मल , सुल्तान सिंह केलुत, बंशीलाल , देवीलाल बिंजरावत, रामेश्वर, गणपत गोराम्बा, सेवाराम बंजारा, जितेन्द्र, पवन बिजरावत, तेजेश्वर मुछाल, सुरेन्द्र, दामोदर, हंसराज, राजूराम सहित बड़ी संख्या में समाजबंधु उपस्थित रहे।

संविदा नर्सिंग कर्मियों का क्रमिक अनशन पाँचवें दिन भी जारी

जयपुर। सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज, जयपुर के गेट नंबर 3 पर संविदा नर्सिंग कर्मियों का आंदोलन मंगलवार को लगातार 39वें दिन भी जारी रहा। जहाँ क्रमिक अनशन के पाँचवें दिन अभिषेक मीणा, प्रदीप चौधरी, रोबिन सिंह, कुश नायक एवं उमा चौधरी ने अनशन किया। अनशनकारियों ने सरकार से संविदा नर्सिंग कर्मियों के साथ हुए समझौते को तत्काल लागू करने की मांग करते हुए कहा कि हमने राज्यपाल से इच्छा मृत्यु की अनुमति मांग कर अपने इरादा साफ कर दिया है, यह आंदोलन हमारे लिए करो या मरो का आंदोलन है, करना सरकार के हाथ है और मरना हमारी मजबूरी हैं, क्यूकि इतने वर्षो की सरकारी सेवा के बाद हमें नौकरी से किस गलती के लिए हटाया गया। हम समाज में किस किस को इसका क्या जवाव देंगे, सामाजिक और आर्थिक प्रताडना सहना हमारे लिए संभव नहीं हैं। हमारे परिवारों के बंद पडे चूल्हों को अब और ज्यादा दिन वर्दास्त नहीं कर सकते। इसलिये या तो सरकार अविलम्ब हमारी सेवाएं बहाल करते हुए अपने वायदा निभाए, अन्यथा हमें इच्छा मृत्यु की अनुमति दे। संयुक्त नर्सेज संघर्ष समिति के सदस्य सचिव हरि सिंह भाटी, बी.पी. सिंह, महिपाल सामोता, अशोक यादव, विमल शर्मा ने कहा कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में नर्सिंग स्टाफ की भारी कमी होने के बावजूद वर्षों से सेवाएं दे रहे अनुभवी संविदा नर्सिंग कर्मियों को सेवा से बाहर रखना अन्यायपूर्ण है। यदि इस सप्ताह निर्णय नहीं हुआ तो राज्य भर से पीडित नर्सेज जयपुर में इकठ्ठा हो कर उग्र आंदोलन के लिए विवश होंगे।

निःशुल्क चिकित्सा शिविर में 100 लाभान्वित

जयपुर। प्रियुष मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल की ओर से गोविन्दपुरा सांगानेर में आयोजित निशुल्क चिकित्सा शिविर में 200 लोगों ने लाभ उठाया। शिविर में न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, हड्डी एवं जोड़ रोग, ईएनटी रोग, फिजियो समेत अन्य विषय के एक्सपर्ट चिकित्सको ने निःशुल्क परामर्श दिया। शिविर संयोजक डॉ. ऊषा गुप्ता ने बताया कि शिविर में डॉ. अजहर कुरैशी, डॉ. निखिल बंसल, डॉ गौरव सक्सेना समेत अन्य चिकित्सको ने अपनी सेवाएं दी। शिविर के दौरान ईसीजी, शुगर, बीपी समेत अन्य जांचे निःशुल्क की गई। डॉ. ऊषा गुप्ता ने शिविर को पूरी तरह सफल बताते हुए कहा कि हॉस्पिटल की ओर से नियमित रूप से इस तरह के आयोजन सामाजिक सेवार्थ आयोजित किए जाते रहते है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने दी 'सदगुरु टेऊँराम जयंती' की शुभकामनाएं

जयपुर। सनातन धर्म के प्रचारक युगपुरुष 1008 आचार्य श्री सदुरु स्वामी टेऊँराम जी महाराज के 140 वे पावन जन्मोत्सव की शुभकामनाएं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश विदेश के समस्त संत महात्माओं श्रद्धालुओं को पत्र के माध्यम शुभकामनाएं दी। पत्र के अंतर्गत मुख्यमंत्री ने आचार्य सदगुरु स्वामी टेऊँराम जी महाराज के पावन जीवन, मानवता की निस्वार्थ सेवा, जन कल्याण, प्रेम ओर करुणा का उल्लेख किया। इससे पूर्व राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी, सिविल लाइन विधायक गोपाल शर्मा ने भी सदगुरु टेऊँराम जयंती की शुभकामनाएं पत्र के माध्यम से प्रेषित की।

लहरिया थीम और सुरों की फुहार से सजी मानसून मेलोडी सीजन-2 की संगीतमय शाम

जयपुर। लीनेस क्लब स्वरा के बैनर तले मानसून मेलोडी सीजन-2 का भव्य आयोजन एम.आई. रोड स्थित एक होटल में किया गया। चार्टर प्रेसिडेंट स्वाति जैन एवं क्लब अध्यक्ष पूनम सक्सेना ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ डॉ. राजीव-अंजू जैन, पियूष जैन और मोनिका जैन ने दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। कार्यक्रम में क्लब की सदस्याओं ने मानसून पर आधारित मधुर एवं सदाबहार गीतों की शानदार प्रस्तुतियाँ देकर समां बाँध दिया। सभी सदस्याएँ लहरिया थीम की आकर्षक वेशभूषा में शामिल हुईं, जिससे पूरे आयोजन का वातावरण रंग-बिरंगा और मनमोहक हो उठा। वहीं सूफियाना गीतों की दिलकश प्रस्तुतियों ने संगीतमय शाम को एक अलग ही ऊँचाई प्रदान की और उपस्थित सभी लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया !! क्लब सचिव रुचि शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम का संयोजन अंजू जैन, निशा शाह, शशि प्रभा जैन, कविता गुप्ता एवं वीणा गुप्ता द्वारा किया गया। अंत में सभी प्रतिभागियों का सम्मान किया गया।

माँ के त्याग को बेटे ने दिया सम्मान-एसडीएम दिनेश बालोत की भावुक तस्वीर बनी प्रेरणा

अधिकारी की कुर्सी पर माँ को बैठाकर जताया सम्मान, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीर

झालावाड़। पिड़ावा के उपखंड अधिकारी (आरएएस) दिनेश बालोत की एक भावुक तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रही है। तस्वीर में वे अपनी माँ को कार्यालय लाकर अपनी अधिकारी वाली कुर्सी पर बैठाते नजर आ रहे हैं। इस भावनात्मक पल को लोगों ने माँ के त्याग, संघर्ष और सम्मान का प्रतीक बताया है। दिनेश बालोत ने तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि, जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि कोई पद या पहचान नहीं, बल्कि वह पल है, जब माता-पिता अपने बच्चे की सफलता पर गर्व महसूस करें। उनका यह संदेश सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और हजारों लोग इसे सराह रहे हैं।

संघर्षों के बीच पूरी हुई माँ की उम्मीद

बताया जाता है कि दिनेश बालोत का बचपन आर्थिक अभावों में बीता। कठिन परिस्थितियों के बावजूद उनकी माँ ने कभी बेटे की पढ़ाई में कमी नहीं आने दी। परिवार की जिम्मेदारियों के बीच उन्होंने अपने कदम पर उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। वर्षों की मेहनत और लगन के बाद दिनेश बालोत का राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आरएएस) में चयन हुआ।

सफलता का सबसे भावुक पल

आरएएस अधिकारी बनने के बाद जब दिनेश बालोत अपनी माँ को कार्यालय लेकर पहुंचे और उन्हें है। अपनी कुर्सी पर बैठाया तो यह पल उनके परिवार के लिए बेहद भावुक बन गया। तस्वीर में माँ के चेहरे पर गर्व और आंखों में छलकती खुशी लोगों को भावुक कर रही है। सोशल मीडिया पर इसे मातृ सम्मान का सशक्त संदेश बताया जा रहा है।

नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा

सोशल मीडिया पर लोग इस तस्वीर को केवल एक भावुक क्षण नहीं, बल्कि नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा मान रहे हैं। लोगों का कहना है कि ऊँचे पद और सफलता हासिल करने के बाद भी माता-पिता के संघर्ष, त्याग और संस्कारों को याद रखना ही सच्ची सफलता है। कि हर उपलब्धि के पीछे माता-पिता का समर्पण, आशीर्वाद और विश्वास सबसे बड़ी शक्ति होती है!

लाठीचार्ज पर घिरी सरकार, संसद से पीएम आवास तक प्रदर्शन

शिक्षामंत्री के इस्तीफे पर अड़े राहुल, पुलिस उन्हें उठाकर ले गई

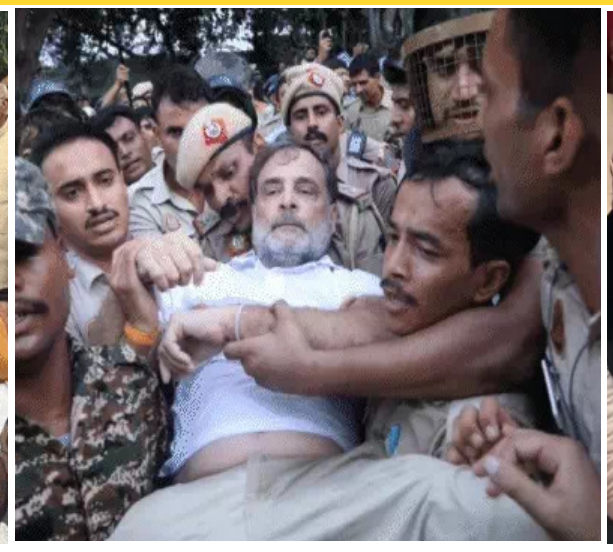

नई दिल्ली। दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर मंगलवार को संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन भी हंगामा हुआ। नीट में गडबडी और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़े विपक्ष के कडे रुख के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार-बार टाली गई। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसद नारेबाजी करते हुए वेल में पहुंच गए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सांसदों से अपनी सीटों पर लौटने और प्रश्नकाल चलने देने की अपील की, लेकिन हंगामा न थमने पर कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। इसके बाद भी गतिरोध जारी रहने पर सदन को पहले 2 बजे और फिर बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। हंगामे के बीच नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर छात्रों पर हुई कार्रवाई और परीक्षा प्रणाली पर विस्तृत चर्चा की मांग रखी। संसद परिसर में मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार छात्रों की आवाज दबा रही है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को सड़क से संसद तक उठाता रहेगा। राज्यसभा में भी यही स्थिति देखने को मिली। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लाठीचार्ज का मुद्दा उठाने का प्रयास किया, लेकिन शोर-शराबे के कारण सदन की कार्यवाही पहले 12 बजे और फिर 2 बजे तक टालनी पड़ी। दोपहर बाद जब सदन दोबारा शुरू हुआ, तब भी स्थिति नहीं बदली। खड़गे ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जैसे ही उन्होंने छात्रों पर हुई कार्रवाई पर बोलना शुरू किया, उनका माइक बंद कर दिया गया। संसद स्थगित होने के बाद विरोध की आंच बाहर तक पहुंची। विपक्ष के प्रमुख नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रधानमंत्री आवास के नजदीक धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारी नेताओं ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई की निंदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग दोहराई।

कॉकरोच पार्टी प्रमुख बोले-बात करना है तो सरकार खुद आए

संसद मार्च में बर्गर खाने वाले प्रवक्ता को हटाया, वांगचुक मेदांता हॉस्पिटल शिफ्ट

नई दिल्ली। दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे अभिजीत दीपके ने कहा कि हमारे प्रतिनिधिमंडल को बुलाकर सरकार ने समय बर्बाद किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके मोबाइल जब्त कर लिए। दोनों एक तरह से जेपी नड्डा के घर नजरबंद थे। इसलिए अब वे सरकार से बात करने नहीं जाएंगे। सरकार को ही जंतर-मंतर पर आना होगा। उधर, दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद सोनम वांगचुक को सफदरगंज से गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया है। सीजेपी ने संसद मार्च के दौरान बर्गर खाने वाले विजेता दाहिया को प्रवक्ता पद से हटा दिया है। दाहिया ने एक वीडियो जारी करके सफाई दी है कि आप मुझे ऐसे जिम्मेदार ठहरा रहे हैं जैसे कि प्रदर्शनकारी होना मेरा काम हो। आपने मुझे इस पद के लिए नहीं चुना है। सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा, हम संसद मार्च आज इसलिए नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि इस सरकार और पुलिस ने छात्रों का खून बहाया है। इन्हें छात्रों की कोई परवाह नहीं है, लेकिन हमें है। सोनम वांगचुक 24वें दिन भी अनशन पर हैं। सोमवार को उन्होंने कहा था- पुलिस की बर्बरता देखने के बाद अपना अनशन जारी रखूंगा। एनडीए संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि पेपर लीक मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी सीजेपी ने ऐलान किया है कि अगर पुलिस ने हिरासत में लिए गए लोगों को तुरंत नहीं छोड़ा तो वे जंतर-मंतर से पुलिस हेडक्वॉर्टर तक एक मार्च निकालेंगे। रात 8 बजे सभी लोग वहां धरना देंगे।

सफदरजंग हॉस्पिटल से वांगचुक का हेल्थ बुलेटिन, उनमें एनिमिया के लक्षण

सोनम वांगचुक को 21 जुलाई 2026 शाम 6:40 बजे सफदरजंग अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। सफदरजंग अस्पताल ने एक बयान में कहा कि डिस्चार्ज के समय उनके वाइटल पैरामीटर्स स्थिर थे। हालांकि, पैनसाइटोपेनिया की समस्या बनी हुई है और उनका सीरम पोटैशियम लेवल 3.4 mEq/L Íæ। यह अपने आप में कोई बीमारी नहीं, बल्कि किसी दूसरी बीमारी या समस्या का संकेत है। इसलिए इसका मूल कारण पता लगाना सबसे महत्वपूर्ण होता है।

सीजेपी के प्रदर्शन में घायल युवती आरएमएल अस्पताल में वेंटिलेटर पर

सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई में घायल हुई 23 साल की छात्रा राम मनोहर लोहिया अस्पताल में वेंटिलेटर सपोर्ट पर है।

एमपी-राजस्थान में मानसून फिर एक्टिव

हिमाचल में अब तक 66 लोगों की मौत; गुवाहाटी में लैंडस्लाइड, असम में 1.7 लाख लोग प्रभावित

नई दिल्ली/भोपाल/जयपुर। जम्मू-कश्मीर में लगातार हो रही बारिश से हालात गंभीर बने हुए हैं। पिछले दो दिनों में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 23 हो गई है। पुंछ और राजौरी के बाढ़ प्रभावित इलाकों में सात लोग अब भी लापता हैं। लगातार बारिश के कारण राहत और बचाव अभियान प्रभावित हुआ। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश से मंगलवार को जनजीवन बुरी तरह प्रभावित रहा। राज्य में अब तक 66 लोगों की मौत हो चुकी है। 145 सड़कें बंद हैं। मौसम विज्ञान विभाग ने कांगड़ा, चंबा और सिरमौर जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। सोमवार को भारी बारिश के बाद असम के गुवाहाटी में लैंडस्लाइड हुई। इसके बाद नेशनल हाईवे-715 का एक हिस्सा पानी में डूब गया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि राज्य के 12 जिलों में 1.70 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। एमपी के लगभग 90% हिस्से में अगले 4 दिन यानी 23 जुलाई तक हल्की बारिश का दौर बना रहेगा। राजस्थान में दो हफ्ते बाद मानसून एक बार फिर एक्टिव होने से जयपुर समेत 33 जिलों में बारिश का अलर्ट है।

असम के बाढ़ प्रभावित गांवों में सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन

सेना ने असम के बाढ़ प्रभावित गांवों में फंसे 571 लोगों को बचाया। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों का जलस्तर बढ़ने से बड़े इलाके में पानी घुस आया है। राजौरी और पुंछ में बारिश के कारण हुई मौतों के बाद जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मृतकों के परिजनों को 6 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की।

अमेरिका ने माना- ईरानी हमलों में 100 सैनिक घायल

कहा- सुरक्षा को देखते हुए देर से जानकारी दी, ईरान के 9 शहरों पर अमेरिकी हमले

तेल अवीव/तेहरान/वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका ने मान लिया है कि ईरान के जवाबी हमलों में उसके करीब 100 सैनिक घायल हुए हैं। पेंटागन के प्रवक्ता सीन पार्नेल ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये सैनिक 7 जुलाई के बाद हुए हमलों में घायल हुए। इनमें से 96% सैनिक ठीक होकर ड्यूटी पर लौट चुके हैं। उन्होंने बताया कि ज्यादातर को सिर पर हल्की चोट लगी थी। पार्नेल ने यह बयान न्यूयॉर्क टाइम्स की उस रिपोर्ट के जवाब में दिया, जिसमें दावा किया गया था कि रक्षा मंत्रालय ईरान के साथ युद्ध में घायल हुए अमेरिकी सैनिकों की जानकारी सार्वजनिक नहीं कर रहा है। पार्नेल ने कहा कि इसमें जानबूझकर देरी हुई। ऐसा सैनिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया गया। उधर अमेरिका और ईरान के बीच लगातार हमले जारी हैं। ईरान ने सोमवार को उन

देशों को निशाना बनाया, जहां अमेरिकी सैन्य ठिकाने मौजूद हैं। इसके जवाब में अमेरिका ने मंगलवार सुबह ईरान के 9 शहरों पर हवाई हमले किए। ईरान की लेबर न्यूज एजेंसी के मुताबिक अबदानान, बंदर अब्बास, बंदर लेंगेह, बुशेहर, चाबहार, केश्म द्वीप, सीरिक, शीराज और कोनारक को निशाना बनाया गया।

ईरानी गृह मंत्री ने पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ से मुलाकात की

ईरान के गृह मंत्री एस्कंदर मोमेनी ने पाकिस्तान दौरे के दौरान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की। सरकारी ईरानी मीडिया के मुताबिक, इस्लामाबाद पहुंचने के बाद यह उनकी दूसरी अहम बैठक थी। इससे पहले मोमेनी ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर से भी मुलाकात की थी। इसके अलावा उनकी पाकिस्तानी गृह मंत्री मोहसिन रजा नकवी से भी बैठक तय थी। मोमेनी का यह दौरा ऐसे समय हो रहा है, जब पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच हुए Mo को फिर से पटरी पर लाने के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज कर रहा है।

हूतियों की चेतावनी- सऊदी बंदरगाहों पर मालवाहक जहाज निशाना बनेंगे

यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने शिपिंग कंपनियों को चेतावनी दी है कि सऊदी अरब के बंदरगाहों पर माल लादने या उतारने वाले जहाज उनके निशाने पर आ सकते हैं। रॉयटर्स के मुताबिक, यह चेतावनी हूतियों के ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस कोऑर्डिनेशन सेंटर की ओर से कई शिपिंग कंपनियों को ईमेल के जरिए भेजी गई। ईमेल में कहा गया है कि ऐसी गतिविधि करने वाले जहाजों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा और वे यमनी सशस्त्र बलों की पहुंच वाले किसी भी क्षेत्र में हमले का लक्ष्य बन सकते हैं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजशकियान ने कहा है कि उनकी सरकार का सुप्रीम लीडर मुजतबा खामेनेई के साथ संपर्क लगातार बढ़ रहा है।

नेपाल में एक रुपए के सिक्के से विवादित-नक्शा नहीं हटेगा

इसमें भारत के इलाकों को अपना दिखाया, नई डिजाइन का प्रस्ताव लौटाया

काठमांडू। नेपाल सरकार ने एक रुपए के सिक्के से विवादित राष्ट्रीय नक्शा हटाने का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। इस नक्शे में भारत के लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया है। नेपाल राष्ट्र बैंक ने पहले प्रस्ताव रखा था कि एक रुपए के सिक्के पर छपे नेपाल के विवादित नक्शे की जगह मुस्तांग के ऐतिहासिक मठ की तस्वीर लगाई जाए। इस नक्शे को सिक्के से हटाने की खबर जैसे ही बाहर आई, इसका विरोध होने लगा। इसके बाद मंत्रालय ने नेपाल राष्ट्र बैंक

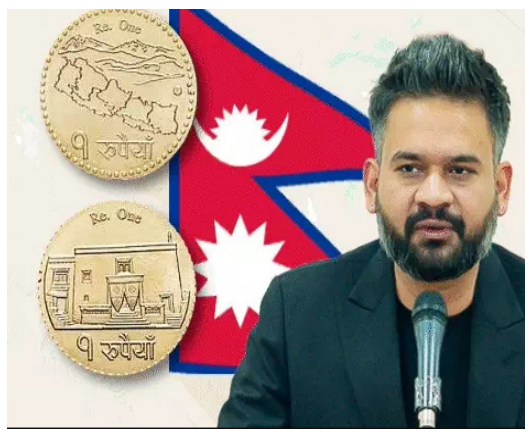

को निर्देश दिया कि डिजाइन में बौद्ध मठ के साथ नेपाल का राष्ट्रीय नक्शा भी शामिल किया जाए। इसके बाद संशोधित प्रस्ताव दोबारा मंजूरी के लिए भेजा जाए। इससे पहले कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि नेपाल सरकार ने एक रुपये के नए सिक्के को मंजूरी दे दी है।

मौजूदा सरकार बनने से पहले ही प्रस्ताव तैयार हुआ

अधिकारियों के मुताबिक, यह प्रस्ताव मौजूदा सरकार बनने से पहले तैयार होना शुरू हो गया था। इसका मकसद नेपाल की मुद्रा पर देश की अलग-अलग सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों को जगह देना था। नेपाल राष्ट्र बैंक के एक अधिकारी ने कहा, नेपाल के कई नोटों और सिक्कों पर पहले से ही पशुपतिनाथ मंदिर और जानकी मंदिर जैसे हिंदू धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों की तस्वीरें हैं। यह महसूस किया गया कि बौद्ध विरासत को पर्याप्त जगह नहीं मिली है। इसलिए घर मठ को चुना गया क्योंकि इसका ऐतिहासिक महत्व बहुत बड़ा है। साथ ही इससे मुस्तांग में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। लो घेकर मठ नेपाल के अपर मुस्तांग में स्थित है। माना जाता है कि इसकी स्थापना आठवीं शताब्दी में गुरु पद्मसंभव (गुरु रिनपोछे) ने की थी। इतिहासकार इसे नेपाल के सबसे पुराने बौद्ध मठों में से एक ही नहीं, बल्कि पूरे हिमालयी क्षेत्र के सबसे प्राचीन बौद्ध मठों में भी गिनते हैं।

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक प्रदीप कुमार सोलंकी द्वारा महानगर मल्टीमीडिया प्रा. लि. जी-848, फेज 3, रीको सीतापुरा, जयपुर (राज.) से मुद्रित एवं 227-हीरालाल की गली, झालाना, मालवीय नगर, जयपुर (राज.) से प्रकाशित।
सम्पादकः प्रदीप कुमार सोलंकी, मो. 93510-01100, Email: atulyasansar@gmail.com संपादकीय कार्यालयः जगतपुरा फ्लाईओवर के पास, जगतपुरा जयपुर।